

Title: Need to include Rajasthani languages in the Eighth Schedule of the Constitution .

श्री पी.पी.चौधरी (पाली) : महोदय, मैं सदन का ध्यान संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ने के प्रस्तावों की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि यह पूरे देश के लोगों की माँग है कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उसी देश में मान्यता मिले। आज हजारों लोगों ने दिल्ली के जन्तर मन्तर पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की माँग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित थीं। समय-समय पर किए गए संविधान संशोधनों के माध्यम से आज 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है भारत सरकार के पास 38 भाषाओं को सम्मिलित करने के प्रस्ताव लम्बित हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा भी एक है। इस भाषा को देश और विदेश में रहने वाले करीब 10 करोड़ लोग बोलते हैं। इस भाषा का अपना साहित्य, इतिहास, सिनेमा और गायन भी है। महात्मा गाँधी जी ने कहा था कि "बच्चा सबसे ज्यादा अपनी मातृभाषा में सीखता है।" यह भी विदित है कि भाषाओं को मान्यता देने में सरकार को कोई बजट आवंटित नहीं करना होता है। राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव वहाँ 2003 में राजस्थान विधान सभा द्वारा संसद को अपनी सहमति के साथ भेज दिया गया था, जिसके बाद सदन में तर्का के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री जी ने 17 दिसम्बर 2006 को भाषा को मान्यता देने के लिए बिल पेश करने का आश्वासन दिया था।

अतः मेरा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि देश भर के लोगों की भावना, सांसदों एवं राज्य सरकार के प्रस्तावों तथा सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों पर गम्भीरता से जल्द निर्णय लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।